

सत्य का ब्रह्मास्त्र

स्वतंत्र बौद्धिकपत्र

सम्पादक-मधुसूदन शर्मा
सह सम्पादक-वृजेश कुमार शर्मा

वर्ष - २ अंक - ४१

सोमवार - ०७/०४/२०२५

पृष्ठ - ४

प्रति सोमवार डिजिटल संस्करण

सम्पादकीय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि नाबालिग के प्राइवेट पार्ट को छूना और सलवार का नाड़ा खींचना रेप की कोशिश नहीं है। यह टिप्पणी उन महिलाओं को हतोत्साहित करने और उनका मखौल उड़ाने जैसी थी, जो यौन उत्पीड़न जैसे अपराध की शिकार हैं और न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट को फिर से दखल देना पड़ा और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगानी पड़ी। यह जितना राहत भरा है, उतना ही चिंताजनक भी। देश की शीर्ष अदालत का हाईकोर्ट के जज को नसीहत देना बताता है कि महिलाओं को लेकर समाज में जितनी संवेदनशीलता होनी चाहिए थी, उतनी है नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि नाबालिग के प्राइवेट पार्ट को छूना और सलवार का नाड़ा खींचना रेप की कोशिश नहीं है। यह टिप्पणी उन महिलाओं को हतोत्साहित करने और उनका मखौल उड़ाने जैसी थी, जो यौन उत्पीड़न जैसे अपराध की शिकार हैं और न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें हिम्मत मिली होगी कि न्याय का पलड़ा उनके पक्ष में है। अदालती फैसले केवल कठघरे तक सीमित नहीं रहते। इनका असर व्यापक समाज पर पड़ता है। इससे भविष्य में अपराधियों को दंड और पीड़ित को न्याय दिलाने में मदद मिलती है। दुर्भाग्य से मौजूदा मामले की एक टिप्पणी अगर कायम रहती, तो आगे चलकर रेप से जुड़े मामलों में महिलाओं को इन्साफ दिलाना मुश्किल हो सकता था। हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया था कि अपराध की तैयारी और उसके प्रयास में मुख्य अंतर केवल इरादे की मजबूती का होता है। गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी गलत बताया।

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्क बिल बना कानून,लागु होने की तारिक केन्द्र तय करेगा मुस्लिम संगठन का विरोध सुप्रीम कार्ट मे छःयाचिका दायर

वक्क बिल 2 अप्रैल को लोकसभ ओर 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घण्टे घण्टे चार्चा के बाद पास

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) बिल को शनिवार देर रात मंजूरी दे दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। यह बिल (अब कानून) 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था।नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक छह याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। नई याचिका केरल के सुन्नी मुस्लिम संगठन केरल जमीयतुल उलेमा ने



दायर की है। वहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है।इससे पहले कांग्रेस सांसद जावेद, एआईएमआईएम

प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आपवक्फ बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शनिवार शाम को वक्फ बिल के विरोध में दो पेज

लेटर जारी किया। ने कहा कि हम सभी धार्मिक, समुदाय-आधारित और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जातेवक्फ संशोधन बिल इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सदभाव और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला है। कुछ राजनीतिक दलों का भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटे को पूरी तरह से उजागर कर दिया है।

एमपी राजस्थान में गर्मी तेज राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। आज सोमवार को 14 जिलों में हीटवेव का अलर्ट है। रविवार को बाड़मेर-जैसलमेर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। पिछले 26 साल में बाड़मेर में अप्रैल के पहले सप्ताह में यह सबसे ज्यादा तापमान है। अगले कुछ दिन गर्म से राहत मिलने की संभावना नहीं है। इधर, राजस्थान से आ रही गर्म हवा के चलते उच्च में भीषण गर्मी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। रविवार को भोपाल का तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इस सीजन में यह सबसे ज्यादा है। प्रदेश के 13 जिलों में तापमान 40 से 42.2 डिग्री के बीच रहा।

ग्रह मंत्री को तीन दिन का जम्मू-कश्मीर दौरा एनसी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ग्रहमंत्री का पहला दौरा

शाह उपराज्यापाल मनोज सिन्हा से मिलेंगे ।



केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज रविवार (6 अप्रैल) से तीन दिन के जम्मू-कश्मीर दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में वे स्वः पर बनी चौकियों पर जाकर हालात का जायजा लेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और विकास कार्यों पर बैठक करेंगे।जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने के बाद यह गृहमंत्री शाह का पहला दौरा है।

शाह सबसे पहले रविवार शाम जम्मू पहुंचेंगे, जहां वे सबसे पहले राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद शाह भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में जाएंगे। जहां वे बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सोमवार को, गृहमंत्री कटुआ जिले में बीएसएफ की सीमा चौकी श्विनयश का दौरा करेंगे और वहां की सुरक्षा स्थिति की जानकारी लेंगे। सोमवार को ही वे जम्मू-कश्मीर पुलिस के शहीद जवानों के परिवारों से मिलेंगे और कुछ को नौकरी के नियुक्ति पत्र भी देंगे। यह कार्यक्रम राजभवन, जम्मू में होगा। मंगलवार (8 अप्रैल) को गृहमंत्री , श्रीनगर स्थित राजभवन में बैठक करेंगे।

मणिपुर में शांति बहली पर दिल्ली में बैठक ,केन्द्र से मिले मैतेई-कुकी समुदाय के प्रतिनिधि राज्य में तेईस महिने से हिंसा जारी ।

२३ महिने से मणिपुर में हिंसा जारी १३ फरवरी २०२५ को राष्ट्रपति शासन लगाया।

केंद्र सरकार ने शनिवार को दिल्ली में मैतेई और कुकी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक का मकसद दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाली और स्थायी शांति स्थापना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सामुदायिक मेल-मिलाप की रणनीति पर चर्चा हुई। मैतेई समुदाय की ओर से ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन और फंडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के 6 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जबकि



कुकी समुदाय की ओर से 9 प्रतिनिधि शामिल हुए। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर ए.के. मिश्रा केंद्र

एशिय को पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज ,पीएम ने नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया

इस ब्रिज क नींव २०१९ मे रखी गई थी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज (नए पम्बन ब्रिज) का उद्घाटन किया। 2.08 किमी लंबे ब्रिज की नींव नवंबर 2019 में मोदी ने ही रखी थी। भाषा विवाद के कारण तमिलनाडु के बड एमके स्टालिन कार्यक्रम में नहीं आए।ब्रज रामेश्वरम (पम्बन द्वीप) को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही नवंबर 2019 में इसकी नींव रखी थी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे डबल ट्रैक और हाई-स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है।स्टील से बने नए ब्रिज

पर पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग की गई है, जो इसे जंग और समुद्र के नमकीन पानी से बचाएगी। पुराना पुल 2022 में जंग लगने की वजह से बंद कर दिया गया था। इसके बाद से रामेश्वरम और मंडपम के बीच रेल कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। रामायण के अनुसार, रामसेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास धनुषकोटी से शुरू हुआ था। इस वजह से ये आस्था के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में 8300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के विभिन्न रेल और सड़क प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया।

सुप्रीम कोर्ट परिसर के छबीस पैडो को ट्रांसप्लांट की मंजूरी ।

60 नए पैड लागाने पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला ।

सुप्रीम कोर्ट भवन के विस्तार के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने परिसर में खड़े 26 पेड़ों के ट्रांसप्लांट की मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत नए कोर्टरूम, कॉन्स्टीट्यूशनल कोर्ट, जजों के चौबंर और वकीलों के लिए अच्छी सुविधाएं बनाई जाएंगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट प्रोजेक्ट डिविजन-1 और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 26 पेड़ ट्रांसप्लांट करने की परमिशन मांगी थी। इसको जस्टिस जस्मीत सिंह की बेंच ने मंजूरी दे दी। इसके बाद अब परिसर में मौजूद 16 पेड़ों को सुप्रीम कोर्ट गेट । और ठ के बीच बगीचे की किनारे वाली जगह पर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। वहीं 10 पेड़ गेट नंबर 1 के पास एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के कोने में शिफ्ट होंगे।

मंजूरी से पहले कोर्ट ने 260 नए पेड़ लगाने का शर्त रखा था – दिल्ली हाईकोर्ट ने पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने की इजाजत देने से पहले 26 पेड़ों के बदले 260 नए पेड़ लगाने की शर्त रखी थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील सुधीर मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि ये सभी 260 पेड़ सुंदर नर्सरी में लगाए जा चुके हैं। हाईकोर्ट ने कहा– ट्रांसप्लांट के लिए ट्री ऑफिसर नया स्पीकिंग ऑर्डर दे –कोर्ट ने कहा कि पेड़ ट्रांसप्लांट को लेकर ट्री ऑफिसर का पहले वाला आदेश (स्पीकिंग ऑर्डर) नहीं माना गया। इस कारण ट्री ऑफिसर को दो हफ्तों के अंदर नया स्पीकिंग ऑर्डर देना होगा। इसमें दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट (क्व्) और पहले के कोर्ट फैसलों के आधार पर पर्मिट देना होगा। पिछले दिनों तेलंगाना में पेड़ काटने का विरोध हुआ, ने हस्तक्षेप किया– पिछले महीने तेलंगाना में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ जमीन पर पेड़ों की कटाई हुई। इसको लेकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बड़ी संख्या में विरोध किया। इस पर जब देशभर में विरोध शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास की जमीन पर किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा– तेलंगाना सरकार को जमीन पर पेड़ों की सुरक्षा के अलावा कोई गतिविधि नहीं करनी चाहिए।

डिजीटल संस्करण

https://sbpatra.in

पर उपलब्ध

सत्य का ब्रह्मास्त्र स्वतंत्र बौद्धिक पत्र

स्वतंत्र बौद्धिक पत्र (समाचार पत्र)

<https://sbpatra.in>

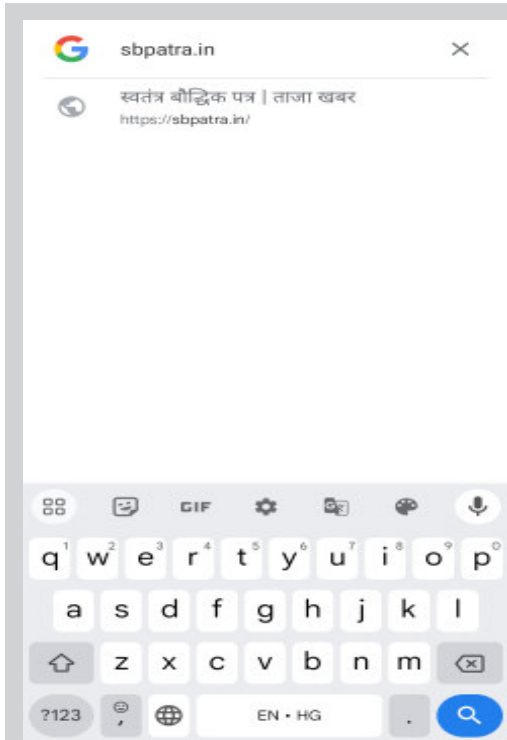
पर डिजिटल संस्करण उपलब्ध



SWATANTRA
BODDDHIK PATRA

खबरों के लिए लॉगिन करें !

<https://sbpatra.in/>



(1)

गुगल सर्च करे - <https://sbpatra.in/>

(2)

होम पेज पर कटेगिरी मे जाए

(3)

ई-पेपर कटेगिरी चुने

(4)

समाचार पत्र आपके सामने क्लिक करे !

निःशुल्क ई-पेपर प्रति सोमवार
को वेब पोर्टल
<https://sbpatra.in/>
से डाउनलोड कर
सकते
हैं।

स्वतंत्र बौद्धिक पत्र (समाचार पत्र)

<https://:sbpatra.in>

पर डिजिटल संस्करण उपलब्ध



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का श्रीलंका में तोपो की सलामी से स्वागत , भारत पीएम ओर श्रीलंका राष्ट्रपति मे द्विपक्षीय मुलाकात

पीएम मोदी तीन दिन को दोरे पर है , यहा मोदी श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायक से मिले।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के तीन दिन के दोरे पर हैं। शनिवार सुबह पीएम मोदी श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायक से मिलने पहुंचे हैं। यहां उनका

मोदी की श्रीलंकाई प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या से भी मुलाकात होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी श्रीलंकाई राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में तमिल समुदाय को ज्यादा अधिकार देने की मांग उठा सकते हैं। इसके अलावा दोनों रक्षा और आर्थिक मामलों पर चर्चा करेंगे। साथ ही पिछले साल हुए द्विपक्षीय समझौते को अंतिम रूप देंगे। इस दौरान उनके बीच मछुआरों और श्रीलंका में रहने वाले तमिल नागरिकों से जुड़े मुद्दे पर बात हो सकती है। पीएम मोदी का यह तीसरा श्रीलंका दौरा है। इससे पहले वे 2015 और 2019 में श्रीलंका का दौरा कर चुके हैं।

पाकिस्तान से भारत आए लोगो के एक जत्थे मे महिला ने भारत भुमि में बच्ची को दिया जन्म माता-पिता ने नाम रखा भारतीय

पाक के सिंध प्रान्त से भारत आए 159 नागरीको मे एक महिला ने बॉर्डर पर ही बच्ची को जन्म दिया ।



भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर एक अनोखा पल देखने को मिला, जब पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भारत आई एक महिला ने अटारी बॉर्डर पर बच्ची को जन्म दिया। गुरुवार को सिंध से 159 हिंदू प्रवासियों

काजत्था वाघा-अटारी बॉर्डर के रास्तभारत पहुंचा। जिनमें माया नाम की गर्भवती महिला भी शामिल थी। भारत में इमिग्रेशन प्रक्रिया के दौरान ही उसे अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। महिला के पति खानू ने तुरंत अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। जिसके बाद बॉर्डर पर मौजूद भारतीय प्रशासनिक अफसरों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे अटारी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ घंटों के इलाज के बाद महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। बच्ची का जन्म भारत की भूमि पर होने के कारण माता-पिता ने उसका नाम 'भारती' रखने का फैसला किया। डिलीवरी के बाद डॉक्टरों ने जच्चा और बच्ची दोनों को पूरी तरह स्वस्थ

बताते हुए अस्पताल से छुटी दे दी। बच्ची के पिता खानू ने बताया कि वे अपने परिवार सहित पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भारत आए हैं। जहां हिंदुओं के लिए हालात दिन-ब-दिन बदतर होते जा रहे हैं।

उन्होंने बताया, हम पाकिस्तान में रोजगार और सुरक्षा की कमी से परेशान थे। वहां हिंदुओं के लिए हालात बहुत खराब हो चुके हैं। धार्मिक उत्पीड़न और बेटियों की सुरक्षा को लेकर हमेशा डर बना रहता था, इसलिए हमने भारत आने का फैसला किया। उनका कहना है कि अब वे भारत में स्थायी रूप से बसने और नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की उम्मीद में हैं।

बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनुस खान से मिले मोदी संबंधो को नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजी से बचने की दी हिदायत

मोदी ने थाईलैंड मे युनुस से बांग्लादेश मे होन्दुओ की सुरक्षा का मुद्दा उठाया ।



प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने की अपील की। साथ ही संबंधों को नुकसान पहुंचाने

वाली बयानबाजी से बचने के लिए भी कहा है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने मोदी-यूनुस से मुलाकात को लेकर जानकारी दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोदी ने यूनुस से कहा कि लोकतंत्र

में चुनाव बहुत जरूरी हिस्सा है। पीएम ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में जल्द ही लोकतांत्रिक और स्थायी सरकार देखेंगे।

दोनों नेताओं के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालत पर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को खुलकर सामने रखा। यूनुस ने भरोसा दिया कि बांग्लादेश सरकार अपनी जिम्मेदारियों पर खरी उतरेगी।

दोनों नेताओं ने थाईलैंड में ठपडैज्म समिट की साइडलाइन में यह मुलाकात की है। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में हुए तख्तापलट के बाद पीएम मोदी पहली बार यूनुस से मिले हैं।

जेलेस्की मिनरल डील से मुकरने की कोशिश कर रहे है , पीछे हटे तो मुश्किल मे पड़ेगे।

ट्रम्प ने रूस को भी दि टैरिफ की धमकी ,



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पर मिनरल डील से पीछे हटने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर जेलेंस्की ने समझौते पर साइन नहीं किए तो उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ट्रम्प ने सोमवार को कहा— हमने रेयर मिनरल पर एक सौदा किया है और अब वह कह रहे हैं कि सौदे पर फिर से बातचीत करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि वह (यूक्रेन) नाटो का मेंबर बनना चाहता है। वैसे, वह कभी भी नाटो का मेंबर नहीं बनने वाला था। जेलेंस्की यह बात जानते हैं। अगर वह मिनरल डील पर फिर से बातचीत करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किलें होंगी।

अमेरिका पर चीना का टैरिफ ट्रम्प का बयान चीन ने घबराकर लगया टैरिफ चीन को भारी पड़ेगा ।

ट्रम्प का दावा चीन ने घबराकर गलत कदम उठाया



34 प्रतिशत जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। नया टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होगा। चीन सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिका का यह कदम अंतरराष्ट्रीय ट्रेड नियमों का उल्लंघन करता है। इससे चीन के कानूनी अधिकार और हितों का नुकसान हो रहा है। यह साफ तौर पर एकतरफा दबाव डालने की कोशिश है। अब अमेरिका आने वाले चीनी सामान पर 54: टैरिफ

जनवरी में सत्ता में लौटने के बाद से ट्रम्प ने अब तक चीन से आने वाले सभी इंपोर्ट्स पर दो बार 10: अतिरिक्त शुल्क लगाए हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह कदम अमेरिका में चीन से अवैध रूप से आने वाले फेंटैनाइल को रोकने के लिए जरूरी था। इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका में आने वाले चीनी सामानों पर प्रभावी रूप से कुल 54: टैरिफ लागू हो गया है। चीन ने 11 अमेरिकी कंपनियों को अविश्वसनीय बताया — शुक्रवार को जवाबी टैरिफ का ऐलान करने के साथ चीन ने 11 अमेरिकी कंपनियों को उन कंपनियों की लिस्ट में डाल दिया है जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इनमें ज़ोन बनाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। इसके अलावा 16 अमेरिकी कंपनियों पर एक्सपोर्ट नियम लागू किए गए हैं, जिससे वे चीनी के दोहरे उपयोग वाले सामान का निर्यात न कर सकें।

न्युक्लियर डील पर ट्रम्प की ईरान को धमकी कहा समझौता करो वरना बमबारी होगी ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को धमकी दी है कि अगर वह अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी समझौते पर नहीं पहुंचता तो अमेरिका उस पर बमबारी कर सकता है। ट्रम्प ने ईरान पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की भी धमकी दी।

ट्रम्प ने आगे कहा— उनके (ईरान) पास एक मौका है, अगर वे ऐसा नहीं करते तो मैं उनपर 4 साल पहले की तरह सेकेंडरी टैरिफ लगाऊंगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिकी और ईरानी अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया। इस बीच ईरान की सेना ने किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया है। जनवरी 2024 में ईरान के तेहरान में एक प्रदर्शनी के दौरान मिसाइलें। (फाइल फोटो) जनवरी 2024 में ईरान के तेहरान में एक प्रदर्शनी के दौरान मिसाइलें। (फाइल फोटो)

तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की मिसाइलें सभी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में लॉन्चरों पर लोड कर दी गई हैं और लॉन्च के लिए तैयार हैं।

तेहरान टाइम्स ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, स्पेंडोरा बॉक्स खोलने से अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 19 आसान शब्दों में स्पेंडोरा बॉक्स खोलना एक मतलब है किसी ऐसी चीज को शुरू करना, जिसके बाद बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाएं, और उन्हें रोकना मुश्किल हो।

चीन ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाया ।

चीन ने भी अमेरिका पर 34: जबाबी टैरिफ लगायारुकहा— ट्रम्प ने ट्रेड नियमों का उल्लंघन किया, ये हम पर दबाव बनाने की कोशिश

चीन ने शुक्रवार को अमेरिका पर 34: जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। नया टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होगा। इससे दो दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने दुनियाभर में जैसे को तैसा टैरिफ लगाया था। इसमें चीन पर 34: अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था। अब चीन ने उतना ही टैरिफ अमेरिका पर लगा दिया है। चीन सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिका का यह कदम अंतरराष्ट्रीय ट्रेड नियमों का उल्लंघन करता है। इससे चीन के कानूनी अधिकार और हितों का नुकसान हो रहा है। यह साफ तौर पर एकतरफा दबाव डालने की कोशिश है।

खबरों के लिए लॉगिन करे

https://sbpatra.in/